Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 160-2016/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2016 (ASVINA 8, 1938 SAKA)

HARYANA GOVERNMENT

INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT

Notification

The 30th September, 2016

No.49/43/2015-4IB1.— The Governor of Haryana is pleased to constitute a Steering Committee for interdepartmental coordination and approvals relating to the Delhi Mumbai Industrial (DMIC) and Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC) with various departments of the Government to achieve the objective set forth for the completion of projects/project under the chairmanship of Chief Secretary, Haryana.

The Committee shall comprise of the following members:-

1.	Chief Secretary	Chairman
2	Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Power Department	Member
3.	Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana, Town & Country Planning Department	Member
4.	Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana, Public Works Department.	Member
5.	Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana, Irrigation Department	Member
6.	Additional Chief Secretary to Govt. of Haryana, Urban Local Bodies Department	Member
7.	Principal Secretary to Govt. of Haryana, Department of Industries & Commerce	Member
8.	Managing Director, Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation	Member Secretary

Any other Administrative Secretary/ Secretaries /Head of Department/ Departments can be invited as a special invitee.

Role & Function of the Committee

1. The Steering Committee would coordinate with various departments and take necessary action to ensure time bound implementation of projects/project.
2. The Committee shall review the decisions taken in the meeting of High Level Monitoring Committee.
3. The committee shall take decision on issues forward to it by the High Level Monitoring Committee.
4. The Head Quarter of the Committee shall be at Chandigarh and it shall hold its meetings as & when required.
5. The Tenure of the Committee shall be up-to the completion of project.
6. TA/DA shall be drawn by the members form their respective departments.

DEVENDER SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Industries & Commerce Department.

HARYANA GOVERNMENT

INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT

Notification

The 30th September, 2016

No.49/43/2015-4IB1.— The Governor of Haryana is pleased to constitute a High Powered Committee (Investments) under the Chairmanship of Chief Secretary, Haryana to materialize Memorandum of Understanding (MoUs) received during the event of Haryana Global Investors Summit pertaining to various departments/ organizations.

The Committee shall comprise of the following members:-

1.	Chief Secretary	Chairman
2.	Administrative Secretary to Government of Haryana, Power Department	Member
3.	Administrative Secretary to Government of Haryana, Transport Department	Member
4.	Administrative Secretary to Govt. of Haryana, Town & Country Planning Department	Member
5.	Administrative Secretary to Govt. of Haryana, Urban Local Bodies Department	Member
6.	Administrative Secretary to Govt. of Haryana, Agriculture Department	Member
7.	Administrative Secretary to Govt. of Haryana, Health Department	Member
8.	Administrative Secretary to Govt. of Haryana, Department of Industries & Commerce	Member
9.	Administrative Secretary to Govt. of Haryana, Education Department	Member
10.	Administrative Secretary to Govt. of Haryana, Renewable Energy Department	Member
11.	Managing Director, Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation	Member Secretary

Any other Administrative Secretary/ Secretaries /Head of Department/ Departments can be invited as a special invitee.

Role & Function of the Committee

1. The High Powered Committee would coordinate with various departments/ organizations to materialize the MoUs by converting these into project/projects of the concerned departments/organizations so as to facilitate investment in the State.
2. To ensure the timely implementation of these project/proposal.
3. The Head Quarter of the Committee shall be at Chandigarh and it shall hold its meetings as & when required.

4. The Tenure of the Committee shall be up-to the completion of project.

5. TA/DA shall be drawn by the members form their respective departments.

DEVENDER SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Industries & Commerce Department.

HARYANA GOVERNMENT

INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT

Notification

The 30th September, 2016

No.49/43/2015-4IB1.— In super-session of the notification bearing No. 49/53/2005-41B-1 dated 8th July, 2005, further partial modification notification bearing No. 49/53/2005-41 B1 dated 14th January, 2008 and super-session of Notification bearing No. 49/33/2013-41B-1 dated 16th April, 2013; constituted Haryana Investment Promotion Board (HIPB) under the Chairmanship Chief Minister, Haryana for the purpose to attract domestic as well as foreign direct investment into the State. Further, as per provision of Enterprises Promotion Policy-2015, Chapter-4 at Sr. No.4.1.1 (a), Haryana Enterprise Promotion Board (HEPB) has been constituted bearing notification No. 49/53/2005-41B1 dated 3rd February, 2016 under the Chairmanship of Chief Minister, Haryana for Time Bound Clearances of new Projects and accelerating the pace of investment in the State, sanction special package for Mega Projects and approving any policy initiative, the Governor of Haryana is pleased to supersede Notification 49/53/2005-41B-1 dated 8th July, 2005, further partial modification notification bearing No. 49/53/2005-41 B1 dated 14th January, 2008 and super-session of Notification bearing No. 49/33/2013-41B-1 dated 16th April, 2013.

Remaining terms and conditions shall remain the same as per Notification bearing No. 49/53/2005-41B-1 dated 3rd February, 2016.

DEVENDER SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Industries & Commerce Department.

हरियाणा सरकार

पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 सितम्बर, 2016

संख्या 1925—प०पा०—2016/11249.— पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 27), की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम हरियाणा पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण (चैक पोस्ट और संगरोध कैम्प, निरीक्षण करने की रीति) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं। (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।	संक्षिप्त नाम।
2. (1) इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगों से बचाव और नियंत्रण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम 27); (ख) "प्ररुप" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न प्ररुप; (ग) "प्रभारी अधिकारी" से अभिप्राय है, किसी चैक पोस्ट या संगरोध कैम्प का पशु चिकित्सक; (घ) ''धारा'' से अभिप्राय है अधिनियम की धारा। (2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हे अधिनियम में दिए गए हैं।	परिभाषाएं।

चैक पोस्ट पर निरीक्षण करने की रीति। धारा 14(1) तथा 15(1)(2).	**3.** किसी चैक पोस्ट का प्रभारी अधिकारी, चैक पोस्ट या संगरोध कैम्प में प्रत्येक पशु का निरीक्षण करेगा तथा सुनिश्चित करेगा कि– (i) पशुओं को ले जाने वाले सभी वाहनों को चैक पोस्ट पर रोका गया है; (ii) उचित कान टैग/चिह्न, उचित स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र तथा टीकाकरण प्रमाण–पत्र रखने वाले पशु को केवल यह सुनिश्चित करने के बाद कि पशु का स्वास्थ्य ठीक है, जाने की अनुमति दी गई है; (iii) पशु जिसे टैग नहीं किया गया है, टीकाकरण प्रमाण–पत्र या स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र के बिना है, को निरोध किया गया है; (iv) निरोध किए गए सभी पशुओं की, संगरोध कैम्प में भेजने से पहले, पशु चिकित्सक द्वारा अच्छी तरह से जांच की गई है; (v) संगरोध कैम्पों पर सभी पशुबाडे, चारा भण्डार पूर्णतयाः स्वच्छ तथा विसंक्रमित किये गए हैं।
संगरोध, कैम्प पर निरीक्षण करने की रीति। धारा 14	**4.** संगरोध कैम्प का प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि– (i) यदि पशु किसी अनुसूचित रोग से पीड़ित हो तथा स्वास्थ्य तथा टीकाकरण अधि–प्रमाणित प्रमाण–पत्र के बिना ही ले जाया जा रहा है, तो ऐसे पशु को संगरोध कैम्प में कम से कम चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा तथा प्ररूप क में पशु मालिक को इस प्रभाव की पावती जारी करेगा; (ii) यदि पशु में किसी रोग का निदान किया गया है, तो ऐसा पशु शरीर में जैविक रोगजनक की प्रविष्टि के बाद उद्भवन अवधि का मिलान करते हुए सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के लिए रखा जाएगा; (iii) पहचान के बाद पशु के कान में टैग/टैटू लगाया गया है, यदि पहले टैग नहीं लगा है; (iv) बाह्य परजीवियों तथा अन्य बीमारियों के लिए पशु का शारीरिक परीक्षण किया गया है; (v) निरोध की अवधि के लिए पशुओं का स्वास्थ्य रिकार्ड रखा गया है; (vi) आवश्यक नमूनों का संग्रहण तथा विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए व्यवस्था की गई है; (vii) जब भी आवश्यक हो खून/मूत्र/मल परीक्षा की गई है और उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; (viii) निरोध के दौरान नश्वरता की घटना में, शव परीक्षण किया गया है और नियमों के अनुसार पशु शव का निपटान किया गया है; (ix) संगरोध में कार्यरत कर्मचारी विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट वर्दी पहनेंगे; (x) खाद्यान, चारा, तथा टीकाकरण पर उपगत खर्च पशु के मालिक द्वारा वहन किया गया है; (xi) इस नियम के अधीन विहित संगरोध अवधि पूरी होने पर पशु को संक्रामक रोगों के विरूद्ध टीकाकरण के बाद छोड़ दिया गया है ।
परमिट का प्ररूप। धारा 14(4).	**5.** प्रभारी अधिकारी स्टेशन से किसी पशु को छोडते समय कुक्कट से अन्यथा पशुओं के लिए प्ररूप ख तथा कुक्कट के लिए प्ररूप ग में परमिट प्रदान करेगा ।
निर्वचन	**6.** यदि इन नियमों के लागूकरण में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो मामला महानिदेशक, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा को निर्दिष्ट किया जाएगा तथा उस पर जिसका निर्णय अन्तिम तथा बाध्य होगा।

रजनी सेखरी सिबल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग।

प्ररूप क

{देखिए नियम 4 (1)}

संगरोध कैम्प अभिरक्षा पावती

प्रमाण पत्र संख्या.....

नीचे वर्णित सभी पशुओं को मैंने दिनांक .....को 14 दिन की अवधि के लिए अभिरक्षा में लिया है।

संगरोध कैम्प का विवरण			
अवस्थिति			
पशु मालिक का विवरण			
पशु मालिक का नाम तथा पता			
पशु जहां से आए हैं			
पशु जहां ले जाने हैं			
	पशु विवरण		
	पशु 1	पशु 2	पशु 3
पहचान संख्या			
जाति			
नस्ल			
आयु			
रंग			
जारी की गई संगरोध कैम्प अभिरक्षा पावती का विवरण			
जारी करने की तिथि			
जारी करने का स्थान			

हस्ताक्षर

(नाम एवं पदनाम)
राज्य पशुचिकित्सा परिषद्/भारतीय पशुचिकित्सा
परिषद् के साथ पंजीकरण संख्या
सरकारी मोहर।

प्ररुप ख

{देखिए नियम 5}

पशु चिकित्सक द्वारा कुक्कुट से अन्यथा पशुओं के लिए प्रदान किया गया परमिट

क सामान्य सूचना (पशुओं के स्रोत)

राज्य जहां से पशु आ रहे हैं ।

स्थान जहां पशु आ रहे हैं ।

ख पशु/पशुओं की पहचान

संख्या

चिह्न

जाति

लिंग

आयु

ग संगरोध विवरण

प्राप्तकर्ता का नाम तथा पता

परिवहन का साधन

बक्सों की किस्म

घ स्वच्छता सूचना

अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता है कि उपरोक्त वर्णित पशुओं का दिनांक..... को मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है।

(क) पशुओं में संक्रामक और ससंर्गजन्य रोग अधिनियम की अनुसूची में वर्णित किसी भी रोग का लक्षण दिखाई नहीं दिया है/दिए हैं ।

(ख) निम्नलिखित अपेक्षाएं पूर्ण करता है/करते हैं:–

1. पशु की पैदा होने की तिथि.....
2. स्थान जहाँ से पशु लाया गया है अनुसूचित रोगों से मुक्त है।
3. पशु उस प्रतिष्ठान से लाया गया है उसका नियमित रूप से पशु प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है।
4. पशु के खून से सम्बंधित प्रयोगिक जांच.....पेशाब/मल.....जिनमें नकारात्मक परिणाम हैं।

स्थान:

तिथि:

हस्ताक्षर

(नाम एवं पदनाम)
राज्य पशुचिकित्सा परिषद्/भारतीय पशुचिकित्सा
परिषद् के साथ पंजीकरण संख्या
सरकारी मोहर।

प्ररुप ग

{देखिए नियम 5}

पशु चिकित्सक द्वारा कुक्कुट (पक्षियों) के लिए प्रदान किया गया परमिट

क सामान्य सूचना (पक्षी/ कुक्कुट के स्त्रोत)

राज्य जहां से पक्षी आ रहे हैं ।

स्थान जहां पक्षी आ रहे हैं।

ख पक्षी/ पक्षियेां की पहचान

संख्या

चिह्न

जाति

लिंग

आयु

ग संगरोध विवरण

प्राप्तकर्ता का नाम तथा पता

परिवहन का साधन

बक्सों की किस्म

घ स्वच्छता सूचना

अधोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता है कि उपरोक्त वर्णित पक्षियों का दिनांक.....को मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया ।

(क) पशुओं में संक्रामक और ससंर्गजन्य रोग अधिनियम की अनुसूची में वर्णित किसी भी रोग का लक्षण दिखाई नहीं दिया है/दिए हैं ।

(ख) निम्नलिखित अपेक्षाएं पूर्ण करता है/करते हैं:–

1. प्रतिष्ठान से लाए जा रहे पक्षी अनुसूचित रोगों से मुक्त हैं।
2. पक्षी उस प्रतिष्ठान अथवा पक्षी उत्पादन केन्द्र से लाए गए हैं, जिनका नियमित रूप से पशु प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाता है।
3. पक्षियों के खून से सम्बंधित प्रयोगिक जांच..... जिनमें नकारात्मक परिणाम है।

हस्ताक्षर

स्थानः
तिथिः

(नाम एवं पदनाम)
राज्य पशुचिकित्सा परिषद्/भारतीय पशुचिकित्सा
परिषद् के साथ पंजीकरण संख्या
सरकारी मोहर।

रजनी सेखरी सिबल,
अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
पशुपालन तथा डेयरिग विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING DEPARTMENT

Notification

The 30th September, 2016

No. 1925-AH-2016/11249.— In exercise of the powers conferred by section 43 of the Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (Central Act 27 of 2009), the Governor of Haryana with the prior approval of the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

Short title and commencement	**1.** (1) These rules may be called the Haryana Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals (Check Post and Quarantine Camp, Manner of Inspection etc.) Rules, 2016. (2) They shall come in force from the date of their publication in the official Gazette.
Definitions	**2.** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, - (a) "Act" means the "Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act, 2009 (Act 27 of 2009); (b) "form" means form appended to these rules; (c) "officer in-charge" means Veterinary Surgeon of any Check Post or Quarantine Camp; (d) "section" means a section of the Act. (2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.
Manner of inspection at check post. Section 14(1)and 15(1)(2)	**3.** An officer-in-charge of a Check Post shall inspect every animal at Check Post or at the Quarantine Camp and shall ensure that,- (i) all vehicles carrying animals are stopped at the Check Post; (ii) only animal having proper eartaging/marking, proper health certificate and a vaccination certificate is allowed to pass after being satisfied that the animal is clinically healthy; (iii) animal who is not being tagged, without vaccination certificate or health certificate, is detained ; (iv) all detained animals are examined thoroughly by the Veterinary Surgeon before shifting to the Quarantine Camp; (v) all the sheds, feed stores at Quarantine Camps are thoroughly cleaned and disinfected.
Manner of inspection at Quarantine Camp. Section14	**4.** An officer incharge of the Quarantine Camp shall ensure that,- (i) in case an animal is suffering from any scheduled disease and is being carried without authenticated certificate of health and vaccination, such an animal is retained in the quarantine camp for a minimum period of fourteen days and acknowledgement to this effect shall be issued to the owner of the animal in Form A; (ii) in case a disease is diagonsed in an animal, such an animal shall be retained for such period, as specified by the Government matching the incubation period after the entry of biological pathogen into the body; (iii) after identification, animal is ear tagged/tattooed, if not earlier tagged; (iv) physical examination of the animal is done for ecto-parasites and other diseases; (v) health record of animals for the period of detention is being maintained; (vi) collection of the necessary samples and arrangement for testing in the specified laboratory are made; (vii) hematological/urine/fecal examination as and when required is carried out, appropriate follow up action, has been taken;

(viii) in the event of mortality during detention, post mortem is conducted and the carcass is disposed off as per rules; (ix) employees working in the quarantine are well uniformed, as specified by the department; (x) expenditure incurred on feed, fodder and vaccination is borne by the owner of the animal; (xi) the animals, having completed the quartintine duration prescribed under this rule, are released after being vaccinated against the infectious diseased.	
5. The officer in-charge shall, at the time of release of an animal from the station, shall grant a permit in Form B for animals other than poultry and in Form C for poultry.	Form of permit section 14(4)
6. If any question arises in implementation of these rules, the matter shall be refered to the Director General, Animal Husbandry and Dairying Department, whose decision thereon shall be final and binding.	Interpretation

RAJNI SEKHRI SIBAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Animal Husbandry & Dairying Department.

FORM A

[See rule 4(i)]

QUARANTINE CAMP CUSTODY ACKNOWLEDGEMENT

Certificate No. .....

All the animals described below have been taken in my custody on this day..... for a period of 14 days.

Details of Quarantine Camp			
Location			
Animal owner details			
Name and address of animal owner			
Animals arrived from			
Animals destined for			
	Animal details		
	Animal 1	Animal 2	Animal 3
Identification number			
Species			
Breed			
Age			
Colour			
Quarantine camp Custody Acknowledgement issue details Date of issue: Place of issue:			

Signature

(Name and designation)
Registration number with state
Veterinary Council/Veterinary Council of India
Official Seal

Form B

[See rule 5]

PERMIT FOR ANIMALS OTHER THAN POULTRY ISSUED BY VETERINARY SURGEON

A. General information (origin of Animal (s)

State from where Animals are coming -

Place from where Animals are coming –

B. Identification of Animal (s)

Number

Mark

Species

Sex

Age

C. Quarantine details

Name and address of consignee

Manner of transport

Type of container

D. Sanitary information

The undersigned certifies that the Animal (s) described above examined on this ------ day by me -

(a) Shows/show no clinical signs of disease mentioned in schedule of Infectious and Contagious Diseases Act.

(b) Satisfies/satisfy the following requirements:-

1. Animal was born on ----------.
2. Place where from animal has come is free from scheduled diseases.
3. The Animal has come from an establishment which is regularly inspected by Veterinary Authority.
4. The Animals were subjected to hematological diagnostic test for ---------- and urine/fecal examination ---------- with negative results.

Place:

Date:

Signature

(Name and designation)
Registration number with state
Veterinary Council/Veterinary Council of India
Official Seal

Form C

[See rule 5]

PERMIT FOR POULTRY (BIRDS) ISSUED BY VETERINARY SURGEON

A. General information (origin of birds/poultry)

State from where birds are coming -

Place from where birds are coming -

B. Identification of bird (s)

Number

Mark

Species

Sex

Age

C. Quarantine detail

Name and address of consignee

Manner of transport

Type of container

D. Sanitary information

The undersigned certifies that the birds described above examined on this day by me -

(a) Shows/show no clinical signs of disease mentioned in schedule of Infectious and Contagious Diseases Act.

(b) Satisfies/satisfy the following requirements:-

1. Birds coming from an establishment, which is/are free from scheduled diseases.
2. Birds came from an establishment or a hatchery which is regularly inspected by Veterinary authority.
3. Birds were subjected to hematological diagnostic test for ----------with negative results.

Place:

Date:

Signature

(Name and designation)

Registration number with state
Veterinary Council/Veterinary Council of India
Official Seal.

RAJNI SEKHRI SIBAL,
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
Animal Husbandry and Dairying Department.

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 सितम्बर, 2016

संख्या पी०एफ०–69/2016/20965.— हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियिम 8) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते है तथा इसके द्वारा, उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है प्रकाशित करते हैं।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि नियमों के प्रारूप पर सरकार द्वारा, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उस के बाद, आक्षेपों तथा सुझावों यदि कोई हो, सहित जो नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा लिखित में प्राप्त किए जाए, विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते है।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 में खण्ड (च) में,

   (i) अंत में विद्यमान ''।'' चिहन् के स्थान पर '';'' चिहन् प्रतिस्थापित किया जाएगा;

   (ii) अंत मे निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्;–

   ''(छ) 'ट्रांजिट ओरंटिड विकास' से अभिप्राय है, कोई विकास, लघु या वृहत जो ट्रांजिट नोड/कोरिडोर के आस पास/साथ साथ संकेन्द्रित है तथा ट्रांजिट सुविधा की पहुंच की सम्पूर्ण सुगमता को साकार करता है, तथा उसके द्वारा लोग परिवहन की निजी प्रणाली के अतिरिक्त पैदल चलने तथा सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को पसंद करने के लिए प्रेरित होते हैं।''।

3. उक्त नियमों में, नियम 8 में, उप–नियम (2) के बाद, अंत में:–

   (i) विद्यमान ''।'' चिह्न के बाद, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

   (ii) निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्;–

   ''परन्तु ट्रांजिट ओरंटिड विकास के अधीन परियोजनाओं के लिए संवीक्षा फीस 1.5/1.75 से 2.5/3.5 तक बढाए गए फर्श क्षेत्र अनुपात के लिए यथानुपात आधार पर प्रभारित की जाएगीः

   परन्तु यह और कि नई एकीकृत लाइसेंसिंग पॉलिसी, 2016 के अधीन संवीक्षा फीस अनुज्ञेय आच्छादित क्षेत्र के लिए प्रति वर्ग मीटर आधार पर लागू होगी।''।

4. उक्त नियमों में, नियम 11 में, उपनियम (1) में,–

   (i) विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

   ''निदेशक को या तो विकास कार्यों की अनुमानित लागत के पच्चीस प्रतिशत के समकक्ष बैंक गारंटी देगा या निदेशक द्वारा यथाअवधारित अनुज्ञप्त भूमि का कोई भाग गिरवी रखेगा तथा अन्तिम रूप में दी गई अनुज्ञप्ति के अनुसार विकास कार्यों को कार्यान्वित करने तथा समापन के लिए प्ररूप एलसी IV में करार करेगाः

   परन्तु दीन दयाल जन आवास योजना के अधीन अफोर्डऐबल प्लाटिड आवासीय कालोनी की दशा में, उपनिवेशक को परस्पर सहमति दरों के अनुसार सम्बद्ध नगरपालिका प्राधिकरण के पास आन्तरिक विकास कार्यों की लागत जमा कराने के लिए विकल्प होगा या अनुकल्पतः विकास कार्यों की अनुमानित लागत के 25 प्रतिशत के समकक्ष बैंक गारंटी जमा कराने के बदले में निदेशक के पक्ष में सभी आवासीय प्लाटों के अधीन कुल क्षेत्र का 15 प्रतिशत गिरवी रखने का विकल्प होगा।''।

5. उक्त नियमों में, नियम 12 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

   ''12क अन्तरणीय विकास अधिकार (टी डी आर) प्रमाणपत्र के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करना। (धारा 6क).–

   (1) आवासीय सेक्टर में या सेक्टर सड़क के संरेखण में या बाह्य विकास कार्यों के लिए निश्चित स्थलों में भूमि रखने वाला कोई भू–स्वामी नियम 8 के उपनियम (2) के अधीन यथाविहित संवीक्षा फीस तथा अनुसूची में दी गई दरों पर लाईसेंस फीस के भुगतान के अधीन रहते हुए अन्तरणीय विकास अधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है। केवल यथाविहित संवीक्षा फीस तथा लाईसेंस फीस अन्तरणीय विकास अधिकार प्रमाणपत्र प्रदान

करने के लिए आवेदन के समय पर उद्गृहणीय होगी। संपरिवर्तन प्रभार, अवसंरचना विकास प्रभार तथा बाह्य विकास प्रभार ऐसे टी डी आर के अन्तरण के लिए अनुमति प्रदान करने के समय पर भुगतान–योग्य होगा।

व्याख्या :–

यहां सेक्टर सड़कों से अभिप्राय है, विकास योजना में निर्दिष्ट सड़कें अर्थात्, 30 मीटर, 45 मीटर, 60 मीटर, 75 मीटर, 90 मीटर या विकास योजना में निर्दिष्ट किसी अन्य चौड़ाई की सड़कें।

(2) टी डी आर प्रमाणपत्र के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु विचारे जाने वाले आवेदन के लिए न्यूनतम क्षेत्र एक एकड़ होगा।

(3) अनुज्ञप्तियां विकास योजना में निर्दिष्ट सभी सेक्टर सड़क अर्थात् 30 मीटर, 45 मीटर, 60 मीटर, 75 मीटर, 90 मीटर तथा विकास योजना में निर्दिष्ट किसी अन्य चौड़ाई की सड़क पर तथा विकास योजनाओं/सेक्टर योजनाओं में परिलक्षित बाह्य विकास कार्यो के लिए निर्दिष्ट स्थलों के संरेखण के अधीन आने वाली भूमियों के लिए प्रदान की जाएंगीः

परन्तु निदेशक अन्तरणीय विकास अधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने की ऐसे अनुमति को अस्वीकार कर सकता यदि वह महसूस करता है कि भूमि का आकार, रूप तथा अवस्थिति उसके उचित उपयोग को न्यायसंगत नही करती है।

(4) ऐसा अनुज्ञप्तिधारी समय–समय पर सरकार, द्वारा यथा अवधारित फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ ए आर) के लिए पात्र होगा।

(5) अन्तरणीय विकास अधिकार प्रमाणपत्र में फर्श क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर) के रूप में विकास अधिकार होगें तथा स्वामी उसी विकास योजना क्षेत्र में अन्य विकासक/ उपनिवेशक को अन्तरणीय होंगे जिसमें स्वामी की भूमि स्थित है जिसके विरूद्व अन्तरणीय विकास अधिकार प्रमाणपत्र के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त किया गया है।

(6) अन्तरणीय विकास अधिकार प्रमाणपत्र ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर तथा ऐसे सिद्धान्तों पर किसी आवासीय सेक्टर में उपयोग किया जा सकता है जैसा समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।

(7) अन्तरणीय विकास अधिकार प्रमाणपत्र की वैधता सरकार द्वारा अवधारित वैधता के अनुसार होगी।

(8) भूमि जिसके लिए अन्तरणीय विकास अधिकार प्रमाणपत्र हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, अन्तरणीय विकास अधिकार प्रमाणपत्र के लिए अनुज्ञप्ति देने के साठ दिन के भीतर या विद्यमान कालोनी के लिए ऐसे अन्तरणीय विकास अधिकार के अन्तरण से पूर्व, जो भी पहले हो, स्वामी द्वारा सरकार को निशुल्क अन्तरित की जाएगी।

(9) निदेशक, भूमि जो अन्तरणीय विकास अधिकार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के कारण उसके पास पहले ही उपलब्ध है, के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करते समय उपनिवेशक को भूमि का विनिमय करने का निर्णय ले सकता है।''।

6. उक्त नियमों में, नियम 13 में,–

(i) अंत मे विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;–

(ii) निम्नलिखित परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात्;–

''परन्तु अफोर्डऐबल ग्रुप आवास कालोनी के विकास के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की दशा में, अनुज्ञप्ति परियोजना के प्रारम्भ की तिथि से चार वर्ष की अवधि से आगे नवीकृत नहीं की जाएगी जो भवन योजना के अनुमोदन या पर्यावरणीय समाशोधन प्रदान करने, जो भी बाद में, की तिथि होगीः

परन्तु यह और कि दीन दयाल जन आवास योजना–अफोर्डऐबल प्लाटिड आवास पॉलिसी, 2016 के अधीन अफोर्डऐबल प्लाटिड आवासीय कालोनी, तथा नई एकीकृत लाईसेसिंग पॉलिसी के अधीन एकीकृत कालोनी के विकास के लिए प्रदान की गई अनुज्ञप्ति की दशा में, विकास कार्य अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तिथि से सात वर्ष (पांच वर्ष आरम्भिक वैधता. दो वर्ष अनुज्ञप्ति के प्रथम नवीकृत की अवधि में अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा तथा यदि और विस्तार मांगा जाता है, तो उसे निदेशक की सन्तुष्टि के अध्यधीन तथा लागू अनुज्ञप्ति फीस के शत–प्रतिशत के समकक्ष नवीकरण फीस के भुगतान पर विचारा जाएगा।''।

7. उक्त नियमों में, नियम 17 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

''17क एक उपयोग से अन्य उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति का स्थानान्तरण,–

(1) अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति का कोई उपनिवेशक तथा/या विकासक, निदेशक की पूर्व अनुमति सहित ऐसे निबन्धनों तथा शर्तो पर जो उस द्वारा अवधारित की जाएं, तिथि, यदि कोई हो, तक ब्याज सहित बकाया नवीकरण फीस के भुगतान पर किसी वर्तमान अनुज्ञप्त परियोजना से अनुज्ञप्ति के किसी अन्य प्रवर्ग/प्रवर्गों को अंशतः या पूर्णतः स्थानान्तरण कर सकता है, किन्तु यह वर्तमान भूमि अनुसूची के क्षेत्र तक सीमित हैः

परन्तु कोई भी तृतीय–पक्षकार अधिकार कालोनी में सृजित नहीं किया गया हो। तथापि, यदि उसे सृजित किया गया हो, तो अनुज्ञप्ति/भूमि उपयोग के अन्य प्रवर्ग के लिए स्थानान्तरण कालोनी के आबंटियों की सहमति से इस सम्बंध में विनिर्दिष्ट सूत्रो के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा जिसे कालोनी के उक्त भाग की सीमा तक तृतीय–पक्षकार अधिकार के गैर–सृजन के रूप में समझा जाएगाः

परन्तु यह और कि क्षेत्र जिस पर तृतीय–पक्षकार अधिकार सृजित किया गया हैं, संहत ब्लाक में होगा, यदि क्षेत्र जिसपर तृतीय–पक्षकार अधिकार सृजित किया गया है, अनुज्ञप्त क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो उपनिवेशक अनुज्ञप्त क्षेत्र के भीतर पुनःस्थापन की विस्तृत स्कीम के साथ उसे संहत ब्लाक में करने के लिए व्यक्तिगत आबंटियों की सहमति प्रस्तुत करेगा।

(2) स्थानान्तरण के अधीन क्षेत्र के लिए भुगतान किए गए बाह्य विकास प्रभारों (मूल राशि तथा ब्याज) को अनुज्ञप्ति में समायोजित किया जाएगा जिसमें उपनिवेशक स्थानान्तरण करता है। उपनिवेशक विद्यमान परियोजना के बाह्य विकास प्रभारों तथा अवसंरचना विकास प्रभारों पर असंदत ब्याज राशि जमा करने के दायित्व से विमुक्त कर दिया जाएगा जिस से वह स्थानान्तरण चाहता है। तथापि, नई अनुज्ञप्ति प्रदान के समय पर बाह्य विकास प्रभारों तथा अवसंरचना विकास प्रभारों की दरें उद्ग्रहणीय होगी।

(3) भुगतान किए गए संपरिवर्तन प्रभार, अनुज्ञप्ति फीस, अवसंरचना विकास प्रभार तथा बाह्य विकास प्रभार समायोजित किएं जाएंगे यदि वर्तमान दर पर स्थानान्तरण के लिए भुगतान की जाने वाली राशि विद्यमान परियोजना की दिशा में पहले भुगतान की गई राशि से अधिक है। इसके अतिरिक्त यदि समायोजन के बाद भी उपरोक्त फीस/प्रभारों का कोई बकाया है तो वह जब्त हो जाएगा। उपनिवेशक द्वारा भुगतान की गई राशि पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(4) यदि उपनिवेशक अपने कालोनी क्षेत्र के भाग को अनुज्ञप्ति के किसी अन्य प्रवर्ग को स्थानान्तरण करने के लिए चयन करता है, तो वर्तमान अनुज्ञप्ति के अधीन रखे गए कालोनी के भाग के क्षेत्र मानदण्डों को मूल अनुज्ञप्ति को प्रदान करने के समय पर चालू लागू क्षेत्र मानकों के छूट के रूप में समझा जाएगा। तथापि, लागू क्षेत्र मानदण्डों, पैरामीटर, सेक्टर क्षेत्र सीमा अर्थात् ग्रुप आवास के लिए 20 प्रतिशत, वाणिज्यिक इत्यादि के लिए 3.5 प्रतिशत अनुज्ञप्ति के भिन्न प्रवर्ग में स्थानान्तरित करने के कारण कालोनी भाग पर लगातार लागू रहेगें अर्थात् कालोनी का भाग जो अनुज्ञप्ति के भिन्न प्रवर्ग को स्थानान्तरण के लिए विचारा गया है, उस तिथि को लागू अनुज्ञप्ति के ऐसे प्रवर्ग के लिए चालू पालिसी पैरामीटर के अधीन अनुज्ञप्ति (जिसमें अतिरिक्त अनुज्ञप्ति शामिल है) प्रदान करने के लिए निश्पेक्ष रूप से पात्र होगा।''।

8. उक्त नियमों में, ''अनुसूची (लाईसेंस फीस की दरे)'' के अन्त में, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्:–

''टिप्पण.– ट्रांजिट ओरंटिड विकास के अधीन परियोजनाओं के लिए अनुज्ञप्ति फीस बढ़ाए गए फर्श क्षेत्र अनुपात के लिए यथानुपात आधार पर उद्गृहीत की जाएगी तथा मिश्रित भूमि उपयोग परियोजनाओं की दशा में उपयोगों के समानुपातिक होगी। नई एकीकृत लाईसेंसिंग पॉलिसी, 2016 के अधीन परियोजनाओं के लिए, अनुज्ञप्ति फीस प्लाटिड कालोनी के लिए विहित दरों की 1.5 गुणा होगी। दीन दयाल जन आवास योजना–अफोर्डऐबल प्लाटिड आवास पॉलिसी, 2016 के अधीन परियोजनाओं के लिए अनुज्ञप्ति फीस मध्यम तथा निम्न क्षमता नगरों के लिए क्रमशः एक लाख रूपए तथा दस हजार रूपए प्रति सकल एकड़ की दर पर उद्गृहित की जाएगी।''।

9. उक्त नियमों में, ''अनुसूची क (अवसंरचना विकास प्रभारों की दर) में, टिप्पण (iii) के बाद, निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे अर्थात्:–

''(iv) ट्रांजिट ओरंटिड विकास के अधीन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना विकास प्रभार बढ़ाए गए फर्श क्षेत्र अनुपात के लिए यथानुपात आधार पर उदगृहीत किए जाएंगे तथा मिश्रित भूमि उपयोग परियोजनाओं की दशा में उपयोगों के समानुपतिक होंगे।

(v) कोई भी अवसंरचना विकास प्रभार दीन दयाल जन आवास योजना–अफोर्डऐबल प्लाटिड आवास पॉलिसी, 2016 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए उद्गृहीत नहीं किए जाएंगे।''।

10. उक्त नियमों में, ''अनुसूची ख (अवसंरचना संवर्धन प्रभार)'' में, टिप्पण के बाद, निम्नलिखित तालिका तथा टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्;–

''ट्रांजिट ओरंटिड विकास पॉलिसी के अधीन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना संवर्धन प्रभारों की दरेंः

तालिका

भूमि उपयोग	दरें प्रति वर्ग मीटर (रुपए में)
1	2
आवासीय	2000
वाणिज्यिक	3000
संस्थागत/आई टी /आई टी ई एस	500

टिप्पण.– अवसंरचना संवर्धन प्रभार मिश्रित भूमि उपयोग परियोजनाओं की दशा में उपयोग के समानुपतिक उदगृहीत किए जाएंगे।''।

श्याम सुन्दर प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 30th September, 2016

No. PF-69/2016/20965.— The following draft of rules further to amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 24 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (Act No. 8 of 1975), is hereby published as required under sub-section (1) of the said section, for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received in writing by the Additional Chief Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department, Chandigarh from any person with respect to the draft of the rules, before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules shall be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Rules, 2016.

2. In the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 2016 thereinafter called the said rules, in rule 2,-

   (i) in clause (f) for the sign '.' existing at the end, the sign ";" shall be substituted;

   (ii) after clause (f) the following clause shall be added, namely:-

   "(g) 'Transit Oriented Development' means any development, macro or micro that is focused around/along a transit node/corridor and facilitates complete ease of access to the transit facility, thereby inducing people to prefer to walk and use public transportation over personal modes of transport.".

3. In the said rules, in rule 8, in sub-rule 2, -

   (i) for the sign ".", existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

   (ii) the following provisos shall be inserted, namely:-

   "Provided that the scrutiny fee for the projects under Transit Oriented Development shall be charged on pro-rata basis for increased FAR from 1.5/1.75 to 2.5/3.5:

   Provided further that the scrutiny fee under the New Integrated Licensing Policy, 2016 shall be applicable on per square metre basis for the permissible covered area.".

4. In the said rules, in rule 11, in sub-rule (1),-

   (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) furnish to the Director either a bank guarantee equal to twenty-five percent of the estimated cost of the development works or mortgage a part of the licenced land, as determined by the Director and enter into an agreement in form LC-IV for carrying out and completion of development works in accordance with the licence finally granted:

Provided that in case of affordable plotted residential colony under Deen Dayal Jan Awas Yojana, the coloniser shall have option to deposit the cost of internal development works with the concerned municipal authority as per mutually agreed rates or in the alternative, shall have option to mortgage fifteen percent of the total area under all residential plots, in favour of the Director, in lieu of depositing bank guarantee equal to twenty-five percent of the estimated cost of development works.".

5. In the said rules, after rule 12, the following rule shall be inserted, namely:-

"12A Grant of Licence for Transferable Development Rights (TDR) Certificate:-

(1) Any landowner having land within the residential sector or within the alignment of sector road or within the sites earmarked for external development works may obtain TDR Certificate subject to payment of scrutiny fee as prescribed under sub-rule (2) of rule 8 and licence fee at the rates given in Schedule. Only scrutiny fee and licence fee as prescribed shall be leviable at the time of application for grant of TDR Certificate. The conversion charges, infrastructure development charges and external development charges shall be payable at the time of grant of permission for transfer of such TDR.

Explanation.—

The sector roads means the roads designated in the development plan i.e. 30 meters, 45 meters, 60 meters, 75 meters, 90 meters or of any other width designated in the development plan.

(2) The minimum area for considering application for grant of licence for TDR Certificate shall be one acre.

(3) Licences shall be granted for the lands falling under the alignment of sector roads designated in the development plans i.e. 30 meter, 45 meter, 60 meter, 75 meter, 90 meter and of any other width designated in development plans and for sites designated for external development works identified in development plans/sectoral plans:

Provided that the Director may refuse such permission to grant licence for availing TDR certificate if he feels that the size, shape and location of the land do not justify its proper utilization.

(4) Such licencee shall be eligible for FAR as determined by the Government from time to time.

(5) The TDR Certificate shall have development rights in the form of FAR and shall be transferable by the owner to other developer/colonizer in the same development plan area wherein the land of the owner is situated against which licence for TDR Certificate has been obtained.

(6) The TDR certificate may be utilized in any residential sector on such terms and conditions and on such principle as may be determined by the Government from time to time.

(7) The validity of TDR Certificate shall be as determined by the Government.

(8) The land for which licence for TDR Certificate has been granted, shall be transferred by the owner free of cost to the Government within 60 days of grant of Licence for TDR Certificate or before transfer of such TDR to an existing colony, whichever is earlier.

(9) The Director may decide to enter into exchange of land with a colonizer at the time of grant of licence for the lands which are already available with him on account of grant of licence for TDR.".

6. In the said rules, in rule 13,-

(i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted: and

(ii) the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that in case of licence granted for development of affordable group housing colony, the licence shall not be renewed beyond period of 4 years from the date of commencement of the project which shall be date of approval of building plans or grant of environmental clearance, whichever is later:

Provided further that in case of licence granted for development of affordable plotted residential colony under Deen Dayal Jan Awas Yojana-Affordable Plotted Housing Policy, 2016, integrated colony under new integrated licencing policy, the development works shall necessarily be completed within a period of 7 years (5 years initial validity + 2 years first renewal of licence) from the date of grant of licence and in case the further extension is sought, then the same shall be considered subject to the satisfaction of the Director and on payment of a renewal fee equal to 100 percent of the applicable licence fee.".

7. In the said rules, after rule 17, the following rule shall be inserted, namely:-

"**17A. Migration of license from one use to other use.-**

(1) Any coloniser and/or developer granted licence under section 3, on payment of the outstanding renewal fee with interest upto date, if any, with the prior permission of the Director, on such terms and conditions as may be determined by him, may migrate from any existing licenced project, partly or fully to any other category/categories of licence, but is limited in scope to the existing land schedule:

Provided that no third-party rights have been created in the colony. However, in case the same have been created, then migration to other category of licence/land use shall be allowed, as per the formulation specified in this regard, with the consent of the allottees of the colony, which shall be deemed as non-creation of third-party rights to the extent of said part of the colony:

Provided further that the area over which third-party rights have been created shall be in a compact block. If area over which third-party rights have been created is scattered over the licenced area then, the coloniser shall submit consent of the individual allottees for making it in compact block along with a detailed scheme of the relocation within licenced area.

(2) External development charges (principal amount and interest) paid for the area under migration shall be adjusted in the licence to which the coloniser migrates. The coloniser would be absolved of the liability to deposit the unpaid interest amount on external development charges and infrastructure development charges of the existing project from which he wants to migrate. However, rates of external development charges and infrastructure development charges at the time of grant of fresh licence would be leviable.

(3) The conversion charges, licence fee, infrastructure development charges and external development charges paid, shall be adjusted in case the amount to be paid for migration at the current rate is more than the earlier paid in case of existing project. Further, if there is any balance of above fee/charges even after adjustment, then the same shall stand forfeited. No interest will be given on amount paid by the colonizer.

(4) If the colonizer opts to migrate part of his colony area to any other category of licence, the area norms of the part of colony retained under the existing licence would be deemed to be in relaxation of the applicable area norms prevailing at the time of grant of original licence. However, the applicable area norms, parameters, sector area limits, viz 20% for group housing, 3.5% for commercial etc. shall continue to be applicable on the colony part being migrated to a different category of licence, i.e., the part of colony that is considered for migration to a different category of licence shall be independently eligible for grant of licence (including additional licence) under the prevailing policy parameters for such category of licence applicable as on date.".

8. In the said rules, at the end of the 'Schedule' (Rates of Licence Fee), the following note shall be inserted, namely:

"Note: The licence fee for the projects under Transit Oriented Development shall be levied on pro-rata basis for increased FAR and shall be proportionate to the uses in case of mixed land use projects. For projects under New Integrated Licencing Policy, 2016, the licence fee shall be 1.5 times the rates prescribed for the plotted colony. The licence fee for the projects under Deen Dayal Jan Awas Yojana-Affordable Plotted Housing Policy, 2016 shall be levied at the rate of rupees one lakh and rupees ten thousand per gross acre for medium and low potential towns respectively.".

9. In the said rules, in 'Schedule-A' (Rate of Infrastructure Development Charges), after note (iii), the following notes shall be inserted, namely:-

"(iv) The infrastructure development charges for the projects under Transit Oriented Development shall be levied on pro-rata basis for increased FAR and shall be proportionate to the uses in case of mixed land use projects.

(v) No Infrastructure Development Charges shall be levied for licences under Deen Dayal Jan Awas Yojana-Affordable Plotted Housing Policy, 2016.".

10. In the said rules, in 'Schedule-B' (Infrastructure Augmentation Charges), after the note, the following table and note shall be inserted, namely:-

"Rates of Infrastructure Augmentation Charges for Projects under TOD Policy:

Table

Land Use	Rates in rupees per square metre
1	2
Residential	2000
Commercial	3000
Institutional/IT/ITes	500

Note: Infrastructure Augmentation Charges shall be levied proportionate to the uses in case of mixed land use projects.".

SHYAM SUNDER PRASAD,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department.

राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा

निर्वाचन सदन, प्लाट नं0–2, सैक्टर 17, पंचकूला

अधिसूचना

दिनांक 30 सितम्बर, 2016

क्रमांक एस0आई0सी0/1एम0इ0/2016/2563.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 24 की उप धारा (2) के अनुसरण करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, नगरपरिषद, सिरसा, जिला सिरसा के 25/09/2016 को सम्पन्न हुये आम चुनाव में निर्वाचित निम्नलिखित सदस्यों के नाम अधिसूचित करता हैः–

वार्ड नं0	निर्वाचित सदस्य का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी	पिता/पति का नाम श्री	वर्ग
1	राजेन्द्र कुमार	रामचन्द्र	अनुसूचित जाति
2	सुनीता	सुशील कुमार	अनारक्षित
3	सुनील बहल	औम प्रकाश बहल	अनारक्षित
4	रणधीर सिह	बलदेव सिंह	अनारक्षित
5	सुमन शर्मा	राजेश कुमार	अनारक्षित
6	ममता	गोपी राम सैनी	महिला
7	मनोज मकानी	राजेन्द्र कुमार	अनारक्षित
8	संगीता	जगदीश	अनारक्षित
9	सुनील	आत्मा राम सहारण	अनारक्षित
10	रेखा	दौलत राम	अनारक्षित
11	जश्न	जवाहर लाल	अनारक्षित
12	नारायण सिंह	लाला राम	पिछड़ा वर्ग
13	कौशल्या देवी	राजेन्द्र कुमार	महिला
14	सुदेश कुमारी	हरभजन सिंह	महिला
15	विकास	मनोहर लाल	अनारक्षित
16	शीला रानी	प्रेम कुमार	महिला
17	रीना सेठी	नितिन सेठी	महिला
18	रेणू बाला	भूषण लाल	अनुसूचित जाति (महिला)
19	नीतू	अमित कुमार	महिला
20	वैशाली	प्रदीप कुमार	अनारक्षित
21	रोहताश कुमार	गिरधारी लाल	पिछड़ा वर्ग
22	बलजीत कौर	हरदास सिंह	महिला
23	राजेश	बन्सी लाल	अनारक्षित

वार्ड नं0	निर्वाचित सदस्य का नाम श्री / श्रीमती / कुमारी	पिता / पति का नाम श्री	वर्ग
24	जगजीत सिंह	औम प्रकाश	अनारक्षित
25	विकास कुमार	राजेन्द्र कुमार	अनारक्षित
26	ख्याली राम	अमर सिंह	अनुसूचित जाति
27	महावीर सिंह	रामेश्वर दास	अनुसूचित जाति
28	सुमनलता	सुनील कुमार	अनुसूचित जाति
29	ज्ञान देवी	राम स्वरूप	महिला
30	रेनु बाला	कर्मजीत	अनुसूचित जाति (महिला)
31	आशा रानी	सुनील कुमार	अनुसूचित जाति (महिला)

पंचकूलाः
दिनांक 30 सितम्बर, 2016.

डॉ० दलीप सिंह,
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA

NIRVACHAN SADAN, PLOT NO.– 2, SECTOR 17, PANCHKULA

Notification

The 30th September, 2016

No. SEC/1ME/2016/2563.— In pursuance of the provisions of Sub-section (2) of Section 24 of the Haryana Municipal Act, 1973, the State Election Commission, Haryana, hereby notifies the names of the following, who have been declared elected, as Members of Municipal Council, Sirsa, District Sirsa in the General Election held on 25th September, 2016-

WARD NO.	NAME OF ELECTED MEMBER Shri/Smt./Km.	FATHER'S/HUSBAND'S Shri	CATEGORY
1	Rajender Kumar	Ramchander	Scheduled Caste
2	Sunita	Sushil Kumar	Unreserved
3	Sunil Bahal	Om Parkash Bahal	Unreserved
4	Randhir Singh	Baldev Singh	Unreserved
5	Suman Sharma	Rajesh Kumar	Unreserved
6	Mamta	Gopi Ram Saini	Women
7	Manoj Makani	Rajender Kumar	Unreserved
8	Sangeeta	Jagdish	Unreserved
9	Sunil	Atma Ram Saharan	Unreserved
10	Rekha	Daulat Ram	Unreserved
11	Jashan	Jawahar Lal	Unreserved
12	Narayan Singh	Lala Ram	Backward Class
13	Kaushalya Devi	Rajender Kumar	Women
14	Sudesh Kumari	Har Bhajan Singh	Women
15	Vikas	Manohar Lal	Unreserved
16	Sheela Rani	Prem Kumar	Women
17	Reena Sethi	Nitin Sethi	Women
18	Renu Bala	Bhushan Lal	Scheduled Caste (Women)
19	Neetu	Amit Kumar	Women
20	Vaishali	Pardeep Kumar	Unreserved
21	Rohtash Kumar	Girdhari Lal	Backward Class
22	Baljeet Kaur	Hardass Singh	Women
23	Rajesh	Bansi Lal	Unreserved
24	Jagjeet Singh	Om Parkash	Unreserved
25	Vikas Kumar	Rajender Kumar	Unreserved
26	Khayali Ram	Amar Singh	Scheduled Caste

WARD NO.	NAME OF ELECTED MEMBER Shri/Smt./Km.	FATHER'S/HUSBAND'S Shri	CATEGORY
27	Mahavir Singh	Rameshwar Das	Scheduled Caste
28	Suman Lata	Sunil Kumar	Scheduled Caste
29	Gyan Devi	Ram Swaroop	Women
30	Renu Bala	Karamjeet	Scheduled Caste (Women)
31	Asha Rani	Sunil Kumar	Scheduled Caste (Women)

Panchkula:
The 30th September, 2016.

DR. DALIP SINGH,
State Election Commissioner, Haryana.

राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा

निर्वाचन सदन, प्लाट नं0–2, सैक्टर 17, पंचकूला

अधिसूचना

दिनांक 30 सितम्बर, 2016

क्रमांक रा0नि0आ0/1एम0इ0/2016/2572.— हरियाणा नगरनिगम अधिनियम, 1994 की धारा 14 की उप धारा (1) का अनुसरण करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा, नगरपालिका कनीना, जिला महेन्द्रगढ के वार्ड नं0 7 से दिनांक 25 सितम्बर, 201 को हुए उप–चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित श्री रोशन लाल पुत्र श्री महादेव (अनारक्षित) का नाम उसके पूर्वाधिकारी की शेष अवधि के लिए अधिसूचित करता है।

पंचकूलाः
दिनांक 30 सितम्बर, 2016.

डॉ० दलीप सिंह,
राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA

NIRVACHAN SADAN, PLOT NO.– 2, SECTOR 17, PANCHKULA

Notification

The 30th September, 2016

No.SEC/1ME/2016/2572.— In pursuance of the provisions of Sub-section (2) of Section 14 of the Haryana Municipal Act, 1973, the State Election Commission, Haryana, hereby notifies the names of Sh. Roshan Lal s/o Sh. Mahadev (Unreserved) who has been elected unopposed as Member from Ward No. 7 of Municipal Committee, Kanina, during the bye-election scheduled for 25th September, 2016, to serve the remaining term of his predecessor.

Panchkula:
The 30th September, 2016.

DR. DALIP SINGH,
State Election Commissioner, Haryana.

54685—C.S.—H.G.P., Chd.